

प्रेषक,

अनूप वधावन,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां,

उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून

दिनांक 12 जून, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 04 (1)/सह0न्या0 /2008-09 दिनांक 01.04.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित वचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रु0 130 हजार (रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-18

2425-सहकारिता आयोजनेत्तर

001-निदेशन तथा प्रशासन

05- सहकारी न्यायाधिकरण

(धनराशि हजार रु0 में)

05-यात्रा व्यय	20
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
18-प्रकाशन	10
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	15
29-अनुरक्षण	5
44-प्रशिक्षण व्यय	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	50
योग	130

(रूपये एक लाख तीस हजार मात्र)

- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को

(एक हजार रु0 में)

8

20

10

15

दिनांक 12 जून, 2008

तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय। देहरादून

6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.3.2008 के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 05- सहकारी न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा। 8-09 (8)

भवदीय,

(अनूप वधावन)  
सचिव।

संख्या 423 /XIV-1/ 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

67, XXVII(1)/2008

8-09 (वीरेन्द्र पाल सिंह) 18

था, प्रशासन अनुसचिव। कारी

निश्चित

8-09 (8)

आज्ञा से,